(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए की रुई उत्पादकों को उ के उत्पाद का उपयुक्त मूल्य मिले, सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) देश में कुछ कपास उपजकर्ता विपणन संघों ने चालू कपास मौसम के दौरान कपास के निर्यात के लिए और अधिक कोटे जारी करने का अनुरोध किया है।

(ख) चालू मौसम के दौरान किसी भी राज्य कपास उपजकर्ता संघ को कपास के निर्यात के लिये कोटे जारी नहीं किये गये हैं । महाराष्ट्र और गुजरात कपास उपजकर्ता विपणन संघों ने क्रमशः कपास की 2 लाख और 1 लाख गांठों के निर्यात कोटों के आवंटन के लिए अनुरोध किया है।

(ग) कपास की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से काफी अधिक हैं और ये पिछले वर्ष के मूल्य स्तर से अधिक है। सरकार ने नवम्बर, 1991 के महीने में निर्यात के लिये बंगाल देशी कपास की 1 लाख गांठों को रिलीज किया था हाल ही में सरकार ने सी सी आई को कुछ पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बगला देश और श्रीलंका की 30,000 गाठों तक कपास की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी है।

इस संबंध में सरकार कपास उपजकर्ता विपणन संघों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

**बाहरी देशों से साड़ियों के आर्डर**

1070. **चौधरी हरि सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बाहरी देशों के नाम क्या हैं जिनमें हथकरघे और विद्युतकरघे पर बनी भारतीय साड़ियों की काफी मांग है ;

(ख) क्या कतिपय बाहरी देशों ने केन्द्रीय सरकार को उत्तम किस्म की साड़ियां तैयार करने के आर्डर दिए थे ; और

(ग) यदि हां, तो इन आर्डरों का बाजार मूल्य कितना था ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) भारतीय साड़ियों की अधिकांशतः मांग यू०एस०ए०, यू०के०; यू०ए० ई०, कनाडा, सिंगापुर, मारीशस, मलेशिया, सऊदी अरब और श्री लंका में है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**कटिहार पटसन मिल का पुनः चालू किया जाना**

1071. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वस्त्र मंत्री 25 नवम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 235 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार (बिहार) स्थित पटसन मिल अभी भी बंद पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसे पुनः चालू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इस बारे में सरकार के सामने क्या-क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं ; और

(ग) इसे कब तक पुनः चालू किए जाने की संभावना है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी०एस०एफ०सी०) जिसने कटिहार जूट मिल की परिसम्पदाओं का अधिग्रहण किया है, उसका पुनरुद्धार करने के लिए मुख्यत: जिम्मेदार है कटिहार जूट मिल के पुनरुद्धार के पैकेज के लिए सभी संबंधित पक्षकारों की पुनरुद्धार पैकेज में निहित राहत, रियायतें तथा उनसे समय-समय पर अपेक्षित त्याग के लिए सहमति प्राप्त करनी होगी । तथापि सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है जो कि कटिहार जूट मिल के पुनरुद्धार के लिए तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य तथा आर्थिक रूप से अर्थक्षम होगा ।

**कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण**

1072. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और किस रूप में ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) से (घ) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत आई० डी० बी० आई० ऋण लेकिन अर्थक्षम एककों के साथ-साथ सुव्यवस्थित एककों को ऊपस्कर/मशीनों के प्रतिस्थापन/नवीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, उत्पाद क्वालिटी में सुधार तथा निर्यात क्षमता में वृद्धि के जरिए आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करता है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत वस्त्र मिलों के नाम सहित उनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न हैं । [देखिए परिशिष्ट 164, अनुपत्र संख्या 23]

**गुजरात में जनता और कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री**

1073. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से गुजरात में जनता और कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार के कपड़े की बिक्री की जा रही है तथा उनका किस्मवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इनकी बिक्री में बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित कंट्रोल साड़ियां, धोतियां,लंबा कपड़ा और पालियस्टर सूती कपड़ा राष्ट्रीय/राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खुदरा विक्रय केन्द्र और गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किया जाता है । हथकरघा जनता साड़ियां और धोतियां गुजरात में कार्यान्वयन अभिकरणों के अपने विक्रय केन्द्रों के अतिरिक्त उपभोक्ता सहकारी समितियों और उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती हैं ।

(ग) और (घ) सरकार को गुजरात में जनता और कंट्रोल कपड़े की बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिका में 1 जुलाई, 1990 से व्यापक संशोधन किए गए हैं जिसमें वितरण व्यवस्था सहित कई कमियों